

प्रेषक,

डी०एस० गर्बाल,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

पौड़ी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: २७ जून, 2016

विषय:—जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय इण्टर कॉलेज, ओजली (खाण्ड्यूसैण) से ब्राह्मण कफलना तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 1.143 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों/मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप वन संरक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान परिसर, देहरादून के पत्र सं०-8बी०/यू०सी०पी०/०६/307/2010/एफ०सी०/1545 दि०-08.10.2015 द्वारा निर्गत विधिवत् स्वीकृति की शर्तों तथा वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दि०-15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय इण्टर कॉलेज, ओजली (खाण्ड्यूसैण) से ब्राह्मण कफलना तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 1.143 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों/मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.286 है० ग्राम-ओजली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-ओजली सिविल सोयम भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तांतरित व नामान्तरित कर दिया गया है। इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। नोडल अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. Digital map with geo-referenced boundaries in respect of forest land proposed for CA in both hard and soft copy, duly authenticated by the DFO may be submitted. For CA area, geo-coordinates at minimum four points along the periphery (polygon) may be shown in the map तथा Geo-referenced map की एक प्रति अभिलेख हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान परिसर, देहरादून को प्रेषित करना आवश्यक होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
6. एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन०पी०वी० देने के लिए बाध्य होगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 62 से अधिक न हो।

10. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
12. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर आवश्यक मृदा संरक्षण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्याबल एवं भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों एवं सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
15. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।
16. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
17. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेंसी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
19. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गब्याल)

सचिव।

पू0प0संख्या- १३१ /XVIII(II)/2016-18(22)/2016 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, लोक निर्माण/वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- उप वन संरक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान परिसर, देहरादून।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)

अपर सचिव।